

on these items. From these amounts how much money had been allotted to each State within these years?

**SHRI P. C. SETHI :** As far as the basic duty on sugar for 1958-1959 was concerned, the duty collected was Rs. 46.52 crores. In the year 1969 the duty collected was Rs. 80.06 crores.

As far as additional duty collected was concerned it was Rs. 13.75 crores for 1968-69 and it is now Rs. 16.75 crores. In the case of tobacco, additional duty collected was Rs. 7.26 crores for 1958-59 and it is now Rs. 23.09 crores. In the case of textiles and other commodities, the additional duty collected was Rs. 21.23 crores. It is now Rs. 22.75 crores.

**SHRI DHIRESWAR KALITA:** My question was about the allocation. My question has not been answered. I wanted to know the amount of duty that was collected on these articles and how much of money had been allotted from these amounts to each State for all these years.

**SHRI P. C. SETHI:** As far as the basic duty is concerned, the funds collected from the basic duty are given to the States as recommended by the Finance Commission. As far as the additional duty is concerned, the additional duty entirely goes to the State Governments after deducting the charges of collection.

**SHRI N. K. SOMANI :** While one may argue for and against the recommendations of the duly constituted body like the Finance Commission, one does not know why so much is stated for an illegitimately constituted sub-Committee of the N. D. C. on such technical and administrative matters. Nevertheless, in view of the difficulties cited, I would like to know whether, when the original system was changed from sales-tax to excise duty, was the N.D.C. at all consulted?

Secondly since a sub-Committee has now been constituted, whether the sub-Committee of the N. D. C. was asked to take public evidence from all interests concerned including the Finance Ministry before coming to a definite decision?

**SHRI P. C. SETHI :** It would not be proper to call the sub-Committee as illegitimately constituted committee of the N. D. C. Even when the system was changed they were consulted. And it was with the concurrence of the State Governments that the changeover was made in

the year 1950. Again when the question was further considered, the Chief Minister was consulted and Dr. B. C. Roy along with the other Chief Ministers went into the question and ultimately recommended that artsilk should be included. Therefore, right from the very beginning, for this changeover, we had consulted the State Governments and even now we want to consult them at their conference.

**Hospitality offers received by officers of finance Ministry from abroad for their sons**

+

\*813. **SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH :**

**SHRI RAM CHARAN :**

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of officers in the Ministry of Finance (Secretariat proper) who received offers of hospitality for their son from foreigners abroad during 1969;

(b) the number of them who sought permission from Government for accepting their hospitality offers on the basis of letters received by them from the foreigners;

(c) the number of cases where the officers' contacts with the foreigners were brought to the adverse notice of Government and also sought to be investigated through the Intelligence Bureau and the result thereof?

(d) the number of cases in respect of whom the permission was granted/refused; and

(e) whether a copy of each of the letter written by the foreigners, on the basis of which permission had been granted/refused will be laid on the Table?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI):** (a) and (b). During 1969, there was one case, where an officer in the Secretariat of the Ministry of Finance applied for permission to accept the invitation extended to his son by a foreign national to spend two weeks' holiday abroad with the latter. After necessary examination, permission was granted.

(c) With respect to the same matter which is referred in reply to parts (a) & (b) of the Question, a communication was received in the Ministry of Finance

and another in the Ministry of Home Affairs, *inter alia*, suggesting the need or a closer check about the contact of this officer with the foreign national, who had extended the invitation. In the second communication received in the Ministry of Home Affairs, the need for an investigation by the Intelligence Bureau was also suggested. But both these communications were received well after the permission had been sought and granted.

(d) There is not other case in the Secretariat proper of Ministry of Finance except the one referred in reply to parts (a) & (b) where any such permission was sought and was granted or refused.

(e) No, Sir.

**श्री चन्द्र शंकर सिंह :** क्या मैं यह जान सकता हूँ कि विदेशी द्वारा लिखे गये जिस पत्र के आधार पर इस अधिकारी को अपने लड़के को बैंकाक भेजने की अनुमति दी गई, उसे लोक हित में सदन की मेज़ पर क्यों नहीं रखा जा सकता ? क्या अध्यक्ष महोदय उस पत्र की कापी को सदन की मेज़ पर रखने की अनुमति प्रदान करेंगे ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस पत्र का जिक्र किया है, वह व्यक्तिगत हैसियत से उस आफिसर के पास आया है। इस सूरत में ऐसे लिखा-पढ़ी के पत्रों को सदन की मेज़ पर रखना मुनासिब मालूम नहीं होता है। (व्यवधान)

**श्री योगेन्द्र शर्मा :** जिस पत्र के आधार पर उस आफिसर के लड़के को बाहर जाने की अनुमति दी गई, क्या वह एक व्यक्तिगत पत्र है ? (व्यवधान)

**SHRI HEM BARUA:** We have copies of the letters. We can disclose the names. A foreigner living in Bangkok called Paul Grandi has written to Shri Parsai, Hindi officer in the department. A complaint against this man was made to Shri Morarji Desai when he was Deputy Prime Minister and Finance Minister. But nothing has been done against this officer. He indulges in astrological rampage. There should be an inquiry into it.

**श्री चन्द्र शंकर सिंह :** यह बात कहां तक सत्य है कि इस आफिसर ने प्रधान मंत्री और

कुछ अन्य मंत्रियों को सोने के यंत्र दिये है और उस से मालूम होता है कि उस के बारे में जांच करने की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** यह बात सही नहीं है कि इस अधिकारी ने मंत्रियों को सोने के यंत्र दिये है। यंत्र से माननीय सदस्य का मतलब ताबीज़ से है। यह बात ठीक है कि पुराने जमाने से इस अधिकारी के परिवार में एस्ट्रोलोजी का धंधा रहा है और वह एस्ट्रोलोजिकल प्रिडिक्शन करते रहे है। जैसा कि मैं ने कहा है कि यह बात सही नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार के ताबीज़ प्रधान मंत्री या किसी मंत्री को दिये है।

**श्री राम चरण :** प्रश्न पूछने से पहले मैं इस अधिकारी, श्री के० बी० परसाई, हिन्दी अधिकारी, का थोड़ा सा इतिहास बताना चाहता हूँ। 1965 में डायरेक्ट्रेट आफ रेवेन्यू इन्टेलिजेंस ने इस अधिकारी को अनफ़िट डिक्लेयर कर दिया था। बाद में उस को मिनिस्ट्री आफ फ़िनांस में अधिकारी बनाया गया। उस का काम है सोने के यंत्र बनाना, जिस की गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। वह फ़ारेनर्ज और मिनिस्ट्रों से गुप्त-दान लेता है। उस ने इन्दौर में दो तीन लाख रुपये की बिल्डिंग बनवाई हुई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि इस पत्र को सदन की टेबल पर नहीं रखा जा सकता है। मैं उस पत्र की दो लाइने पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ। यह 7 अप्रैल, 1969 का पत्र है, जिस को श्री पाल भेंडी ने श्री परसाई को लिखा है। उस में लिखा है :

“Business now is also getting better and I know that I will make it”.

“The milk account has'nt come through yet but I think if that company will use advertising as sales builder, PAG will get the account.”

इस में जो मिल्क एकाउन्ट की बात लिखी है, यह मिल्क-एकाउन्ट क्या है, क्या यह सोने की बाबत है... (व्यवधान)...

**श्री सुरज भान :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ़ आर्डर है । जिस पत्र से श्री रामचरण जी कोट कर रहे हैं, उसे टेबल पर रखा जाय ।

**SHRI S. KANDAPPAN :** There is a general rule that when documents of such a nature are quoted, they have to be laid on the Table of the House.

**श्री राम चरण :** उन्होंने आगे चल कर उसी लेटर में कहा है—

“.....things sure did not look too rosy. Business taking a good turn now however.....”

मैं यह जानना चाहता हूँ कि मैंने उस पत्र की जो बात कही है, क्या यह उस पत्र में मौजूद है या नहीं ? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इनका कोई लिंक बँगकाक के या अन्य देशों के फौरन-स्मगलर्स से है या नहीं ? जिन अधिकारी का नाम मैंने यहां पर लिया है, उन का पेशा क्या है और जैसा मेरे एक साथी ने अभी कहा है कि सोने के यन्त्र (तावीज़) बना कर मिनिस्ट्रों, डिप्टी-मिनिस्ट्रों और प्राइम मिनिस्टर को देते हैं—मैं उसकी डिटेल् में नहीं जानना चाहता हूँ—क्या इनको सरकार ने प्योर गोल्ड अपने पास रख कर यन्त्र या जादू के तावीज़ बना कर मार्केट में बेचने की इजाजत दी है तथा क्या सरकार इस सारे आस्पेक्ट्स पर विचार करने के लिये कोई कमेटी सेट-अप करेगी ?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या इन्होंने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जिन पांच-छः एम० पी० ने इनके खिलाफ़ शिकायत की है उनके खिलाफ़ सूट फाइल करने के लिये इनको इजाजत दी जाय ?

**श्री प्र० स० सेठी :** जहां तक सोने के यन्त्र या तावीज़ का प्रश्न है, एक और प्रश्न भी पूछा गया है कि इन के पास सोने के यन्त्र और तावीज़ है या नहीं । मैंने उत्तर में बताया है कि इन के पास सोने के तावीज़ है . . .

**डा० राम सुभग सिंह :** किन के पास है ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** जो हिन्दी आफिसर श्री परसाई है, उन के पास है । . . . (व्यवधान) . . . जहां तक यह प्रश्न है कि वे सोने का तावीज़ किसी को देते हैं या नहीं देते हैं—यह बात मेरी जानकारी में पहली बार आई है, मैं इसकी जानकारी लूंगा । लेकिन जैसा मैंने बताया था, इस प्रकार का कोई तावीज़ उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया है ।

जहां तक प्रश्न है कि उन के पास कोई पत्र विदेश से आया है—आप जानते हैं कि एस्ट्रो-लोजी के बारे में कुछ कमजोरी यहां भी लोगों को होती है, हो सकता है कि उसी तरह की कुछ कमजोरी विदेश के लोगों को भी हो, और उसी की वजह से उन का कुछ ताल्लुक हो ।

**श्री राम चरण :** जो लेटर मैंने कोट किया है उस को आप टेबिल पर रख दीजिये, उस से असलियत जाहिर हो जायेगी । उस से जाहिर होता है कि उन का स्मगलर्स के साथ लिंक है उस पत्र की लैंग्वेज इस बात को जाहिर करती है—लेकिन उसको आप छिपाना चाहते हैं ।

**श्री प्र० च० सेठी :** अब तक उन के खिलाफ़ जो शिकायतें आई हैं, उस में उन का स्मगलर्स के साथ कोई लिंक है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है । माननीय सदस्य ने पहली बार यह सवाल यहां पर प्रस्तुत किया है, हम इस की छानबीन करेंगे ।

**श्री राम चरण :** क्या आप उन 5 एम० पी० के नाम दे सकते हैं, जिन्होंने राइटिंग में आपको लेटर दिया है और जिन के खिलाफ़ उन्होंने सूट फाइल करने की परमीशन मांगी है . . . (व्यवधान) . . . आप हमारी पूरी बात सुन लीजिये . . . (व्यवधान) . . .

**SHRI HEM BARUA :** There were various allegations of corruption against this officer. You should enquire into these charges.

**The Prime Minister, Minister, of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (SHRIMATI INDIRA GANDHI) :** My colleague has said that this particular allegation

had not been made before. Now that it has been made we shall certainly look into it..... (Interruptions)

**SHRI CHAITAMANI PANIGRAHI :** This is one of the many instances in which foreign patronage is being used to sabotage the national economy in various ways. Is the hon. Minister aware of the fact that among the board of directors of the International Ore and Fertiliser Company are the ex-Secretary of the Ministry of Finance, ex-Chairman of the Union Public Service Commission, ex-Joint Secretary of the Home Affairs, ex-Chairman of the National Mineral Development Corporation, Bilgrami and the Managing Director is one Mr. Rahmatulla, and that they have close contact with the Secretary, Ministry of Foreign Trade and this is how they are trying to sabotage the fertiliser policy of the Government of India because of their contacts with foreign firms in America? I should like to know whether the Government would enquire into this matter and place their findings before the House.

**SHRI P. C. SETHI :** This particular matter does not arise out of this question.

**SHRI CHINTAMAN IPANIGRAHI :** It arises because the ex-Secretary of the Ministry of Finance is there.

**SHRI P. C. SETHI :** I shall point out to the House that the person concerned is not in charge of any administrative work; he is doing Hindi translation of English versions; therefore *prima facie* it does not appear to be a case where an officer.... (Interruptions) ... The Prime Minister said and I have also said that now that certain hon. Members have raised a few questions we shall certainly look into that matter and make further enquiries. .... (Interruptions.)

**MR. DEPUTY -SPEAKER :** The Question Hour is over.

**श्री सुरज भान :** इन्होंने दो लाख रुपये के इन्दौर में मकान बनाये हैं, एक मकान इन के नाम है और एक इन की बीबी के नाम है—इस बात से अन्दाज़ा लगाया जा सकता है... (व्यवधान) ...

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Order order. Shri Viswambharan. Several Hon. Members rose—

**SHRI HEM BARUA :** The best thing is to dismiss this man from the Ministry. (Interruption).

**SHRI KANWAR LAL GUPTA :** Sir, I want to raise a point of order.

**MR. DEPUTY SPEAKER :** Let me hear one by one. Order, order.

**SHRI K. LAKKAPPA :** Let a half-an-hour discussion be held on this.

**MR. DEPUTY SPEAKER :** There are ways open to you, Mr. Lakkappa. I am only guiding the proceedings of the House. It is 12 O'clock now and that is why I am passing on to the next item.

**श्री कंवर लाल गुप्त :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि जो क्लक हैं उनके मुताबिक 12 बजे तक सदन में सवाल पूछे जा सकते हैं लेकिन आपने दो तीन मिनट पहले ही सवालों का समय समाप्त कर दिया...

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** I am not looking to the clocks there. I am looking to the time-piece on my table.

**श्री कंवर लाल गुप्त :** आपको इस तरह से मिनिस्टर को शील्ड नहीं करना चाहिए, यह गलत तरीका है। प्राइम मिनिस्टर चुपचाप बैठे मुन रही है, वह यह कहें कि फुलफ्लेज्ड इन्क्वायरी होगी। मैं यह मांग करता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर कहें कि पूरी इन्क्वायरी होगी। वे इन्क्वायरी क्यों नहीं कराना चाहती है?... (व्यवधान) ...

**SEVRERAL HON. MEMBERS** rose,—

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** If you are not satisfied with the answers, there are many ways open to you and you can resort to them.

**SHRI K. LAKKAPPA :** This is a very important question. Many officers are involved in it, and you are not allowing any more supplementaries. (Interruption).

**MR. DEPUTY-SPEAKER :** Mr. Lakkappa, you can kindly write and it may then be considered.

**SHRI PILOO MODY:** Sir, I would like to know how many ways are open to synchronise your watch with the rest of the clocks in the House.

**MR. DEPUTY-SPEAKER:** That can be looked into. There may be a mechanical failure. I admit machines can fail, and human beings can fail.

**SHRI KANWAR LAL GUPTA:** Let them make an enquiry against the officer. (*Interruption*).

Several Hon. Members *rose* —

**SHRIMATI INDIRA GANDHI :** I thought that I had clearly stated that some allegations were made and they have sent to us and they were looked into. Now, quite different ones have been made, and also, it has been pointed out that some sentence in that letter may have another meaning: it may be code or something. I have stated very clearly that these matters will be enquired into. (*Interruptions*).

**SHRI K. LAKKAPPA:** Many senior officers are involved in it. No action has been taken.

**MR. DEPUTY-SPEAKER** Order, order.

### SHORT NOTICE QUESTION

#### **Introduction of Central Industrial Security Force in Cochin Division of F. A. C. T.**

S.N.Q. 13. **SHRI P. VISWAMBHARAN:** Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the Fertilizers and Chemicals, Travancore Limited has decided to introduce Central Industrial Security Force in the Cochin Division of the Company;

(b) whether notices have been issued to the employees in the Security and Fire Department in the Cochin Division informing that the same Department will be abolished; and

(c) whether the employees have represented to the management of the Fertilizers and Chemicals, Travancore and Government against the introduction of the Central Industrial Security Force and requesting that they should be retained in vice?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND MINES AND METALS (SHRI D. R. CHAVAN):** (a) and (b). FACT has proposed that the Central Industrial Security Force Act, 1968 be applied to the Cochin Fertilizer Project. Accordingly the security and fire-fighting staff have been requested to give their option to join the Central Industrial Security Force.

(c) The FACT Cochin Division Employees Union have represented to the management against the introduction of Central Industrial Security Force. Government of India have not received any representation.

**SHRI P. VISWAMBHARAN:** The last sentence of his reply, if I heard him aright, was that the Government of India have not taken a final decision on this.

**SHRI D. R. CHAVAN:** I said, Government of India has not received any representation from the employees' union.

**SHRI P. VISWAMBHARAN:** On the 9th March this year, the Personnel Manager of the Cochin division of FACT had issued a memo to all the members of the Security and Fire Department of that division in which it has been said that the Government have decided to introduce the Central Industrial Security Force in the FACT, Cochin division, immediately, and the Staff belonging to this department have been asked to give their option on or before 12th March. The memo was issued on 9th March and they were given time for giving the option till 12th March. That means, they were asked to give their option within three days whether they are prepared to opt for the Central Industrial Security Force or to be retrenched. In this connection, I am at a loss to understand why such an urgent situation has arisen in that factory. Section 14 of the Central Industrial Security Force Act says that any section of this force could be sent on deputation to a public undertaking on the request of the managing director of that public undertaking, showing the necessity thereof, Sub-clause (2) of the same section says that this force may be withdrawn when that situation ceases to exist. To my knowledge, there is no serious situation there in Cochin. Now, I would like to ask certain questions. I want to know whether the management of FACT has requested the Inspector General of this Central Industrial Security